नितिन नबीन व भजनलाल ने पंचायतों के लिये 60 प्रचार रथ रवाना किये

पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर सेवा संकल्प सभा में जनप्रतिनिधियों को जनता से सीधा सम्पर्क रखने की सीख दी

जयपुर, 25 सितंबर। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को मिली सफलता के बाद अब पार्टी ने आगामी पंचायतीराज चुनावों की तैयारियों का बिगुल बजा दिया है। शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर जयपुर के दादिया में आयोजित

- **सेवा संकल्प सभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिये 2636 करोड़ रुपये के निकाय कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया।**

जयपुर के दादिया में आयोजित सेवा संकल्प सभा को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया।

"सेवा संकल्प सभा" में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं एवं नवनिर्वाचित निकाय जनप्रतिनिधियों को जनसेवा का मंत्र देते हुए पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटने का आव्हान किया। इसी कार्यक्रम के दौरान 90 प्रचार रथों को पंचायतों के लिए रवाना किया गया। इन रथों के माध्यम से केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा विकास कार्यों की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का अभियान चलाया जाएगा।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की भावना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में विधायक, सांसद तथा निकाय एवं पंचायतीराज के जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उनका जनता से सीधा संपर्क होता है। थ्री-टियर सिस्टम के जनप्रतिनिधि ही सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचा सकते हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनता के सुख-दुख में भागीदार बनना ही जनप्रतिनिधि की सार्थकता है।

मुख्यमंत्री ने निकाय चुनाव में जीतकर आए जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संदेश देते हुए कहा कि सरकार के विकास कार्यों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।

सेवा संकल्प सभा के दौरान राज्यसभा सांसद नितिन नबीन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए 2636 करोड़ रुपए के 929 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

इसी कार्यक्रम में, विभिन्न योजनाओं के 36 लाख लाभार्थियों के खातों में 400 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई।

मुख्यमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसके बाद दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 2:05 बजे राजकीय महाविद्यालय ऑडिटोरियम पहुंचेंगे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रतापगढ़ के कार्यक्रमों के बाद, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से उदयपुर के लिए रवाना होंगे। शाम 4 बजे वे रुपिस रिजॉर्ट, उदयपुर में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शाम को जयपुर लौट आएंगे।

कोचिंग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और पूर्व अतिरिक्त इनकम टैक्स कमिश्नर होने का हवाला देते हुए बड़े बदमाशों से संपर्क होने की बात भी कही। शिकायत में आरोप है कि डागुर ने यह भी धमकी दी कि तीनों को इस तरह मरवाया जाएगा कि उनके परिजन भी पहचान नहीं पाएंगे।

ज्ञानेश कुमार और उनके ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जोड़ना, नाम हटाना और फिर बहाल करना, फॉर्म 6 में बदलाव, अपील दाखिल करना तथा मतदाता डेटाबेस और आईटी सिस्टम का केन्द्रीयकरण शामिल था।

एक नोट में संधू ने कुछ कार्रवाहियों को "अनधिकृत और गैरकानूनी" बताया। दोनों चुनाव आयुक्तों ने काम के बंटवारे में किए गए ऐसे बदलावों को लेकर कैबिनेट सचिव को भी अलग-अलग पत्र लिखे, जिससे मतदाता सूची टैक्नोलॉजी पर उनकी निगरानी कम हो गई थी। ईसीआई का कहना है कि सभी महत्वपूर्ण फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे और अलग-अलग राय होना विचार-विमर्श की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है।

एक अन्य विवाद ने भी और अधिक ध्यान खींचा है। ज्ञानेश कुमार की बेटी और नोएडा की जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम को लेकर नए सवाल उठे हैं। वकीलों के एक संगठन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इलाहबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली मेधा रुपम की याचिका को सुप्रीम कोर्ट में "बारी से पहले" (आउट-ऑफ -टर्न) लिस्ट किए जाने (सुनवाई सूची में शामिल करने) पर सवाल उठाया है। हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा एवं ऐक्टिविस्ट आकृति चौधरी की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (नैशनल सिक्योरिटी एक्ट) के तहत हिरासत को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने रूपम और अन्य अधिकारियों के वेतन से 5 लाख रुपये का मुआवजा वसूलने का आदेश दिया था और उनके आचरण की कड़ी आलोचना की थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस वसूली के आदेश पर रोक लगा दी। आलोचकों ने इस प्रक्रिया के औचित्य पर सवाल उठाते हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ उनके रिश्ते का उल्लेख किया है। इस बीच, विपक्षी नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के महाभियोग की मांग और तेज कर दी है। आंतरिक आपत्तियों का हवाला देते हुए और "एक व्यक्ति के तानाशाहीपूर्ण नियंत्रण" का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, डैरेक ओ'ब्रायन, उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल सहित, कई नेताओं ने उन्हें हटाने की मांग की है। कुछ नेताओं ने उनकी गिरफ्तारी और हाल के चुनावों को रद्द करने की भी मांग की है। अप्रैल में राज्यसभा के 73 सांसदों द्वारा हस्ताक्षिरत एक नोटिस, जिसमें "साबित कदाचार" के आधार पर उन्हें हटाने की मांग की गई थी, अभी लंबित है। विपक्ष एक नया प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। ईसीआई लगातार अपनी प्रक्रियाओं का बचाव कर रहा है, लेकिन इन सभी विवादों के एक साथ सामने आने से, संस्था (चुनाव आयोग) की विश्वसनीयता को लेकर सवाल और गहरे हो गए हैं।

ज्ञानेश कुमार के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने की ओर ध्यान दिलाया।

घोष ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इस समय भारत में जो हो रहा है, उस पर पूरी दुनिया को ध्यान देना चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्रामों का इस्तेमाल बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से व्यवस्थित तरीके से हटाने के लिए किया गया है। लेकिन भारत की ज़ी इस बात को समझ गई है और अब स्थिति बदल रही है।

एक अन्य समानान्तर घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा कथित तौर पर, दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना, लिए गए फैसलों, जारी दिशा-निर्देशों और सॉफ्टवेयर में किए गए बदलावों को चुनौती दी गई है।

अधिवक्ता शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी द्वारा अधिवक्ता चांद कुरैशी के माध्यम से दायर याचिका में मांग की गई है कि ऐसे फैसलों को असंवैधानिक, मुख्य चुनाव आयुक्त की शक्तियों से बाहर और अमान्य घोषित किया जाए।

एक अन्य अधिवक्ता, बृजेश सिंह ने गुरुवार को अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से सुप्रीम कोर्ट की कथित अवमानना के लिए सीईसी कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की वैधानिक अनुमति मांगी।

यह याचिका "द इंडियन एक्सप्रेस" की उन खोजी रिपोर्टों के कुछ दिनों बाद दायर की गई, जिनमें बताया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने तीन सदस्यीय चुनाव आयोग के नाम पर कथित तौर पर लिए गए कई फैसलों पर लिखित आपत्तियां दर्ज की थीं। त्रिपाठी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 18 का भी हवाला दिया है। इस धारा में चुनाव आयोग द्वारा निर्णय लेने की व्यवस्था बताई गई है और कहा गया है कि यदि किसी मुद्दे पर मतभेद हो, तो बहुमत की राय मान्य होगी।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग में तीन चुनाव आयुक्त होते हैं। सीईसी उनमें समान लोगों में प्रथम यानी (फर्स्ट अमंग इक्वल्स) होता है, न कि सबसे वरिष्ठ सदस्य। जहां तक संभव हो, फैसले तीनों की सर्वसम्मति से लिए जाने होते हैं।

अमेरिका के खिलाफ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चुकानी होगी। सी ई ए ने कहा कि जियोपॉलिटिक्स और अर्थव्यवस्था के बीच बढ़ते संबंधों ने वैश्विक आर्थिक वातावरण को बुनियादी रूप से बदल दिया है। आपूर्ति में व्यवधान, व्यापार प्रतिबंध और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं की कमजोरियां नीति-निर्माताओं के लिए लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही हैं।

नागेश्वरन ने कहा कि नीति-निर्माताओं को 1980 से 2020 के दौर में हावी रहे आर्थिक नीति, ढांचे के आगे बढ़ने की जरूरत है, जब मांग प्रबंधन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता था।

उन्होंने कहा, अब यह मांग प्रबंधन का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह आपूर्ति प्रबंधन का मामला है।

उन्होंने वैश्विक व्यापार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े उत्पादों के बढ़ते महत्व को भी रेखांकित किया और कहा कि व्यापार का इस्तेमाल अब तेजी से रणनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है।

नागेश्वरन ने कहा, व्यापार को हथियार बना दिया गया है, कुछ मामलों में विकल्प न होने के कारण प्रतिक्रिया के रूप में और कुछ मामलों में आक्रामक आधार पर।

सी ई ए ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने तत्काल तीन चुनौतियों की पहचान की-अमेरिका के साथ भारत के अस्थिर संबंध, वैश्विक ऊर्जा बाजारों में हो रहे बदलाव और ए आई इकोसिस्टम में भारत की अपेक्षाकृत सीमित मौजूदगी।

उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि ए आई इकोसिस्टम में भारत की कोई भूमिका नहीं है, बस बौद्धिक संपदा अभी उतनी नहीं है। यह वास्तविक समस्या है, लेकिन यह आएगी।

उन्होंने कहा कि यह मानकर नहीं चला जा सकता कि वैश्विक बाजार हमेशा जरूरी वस्तुओं और इनपुट तक निर्बाध पहुंच उपलब्ध कराते रहेंगे। आपको खुद उत्पादन करना होगा क्योंकि दुनिया आपको आपूर्ति नहीं करेगी।

उनकी टिप्पणियां इस बात को रेखांकित करती हैं कि भारत के लिए घरेलू उत्पादन, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं और रणनीतिक विविधीकरण का महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि देश तेजी से विभाजित होते वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक परिदृश्य के बीच आगे बढ़ रहा है।

नागेश्वरन की यह स्वीकारोक्ति वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता हो चुका है और मामला निपट गया है तथा वाशिंगटन द्वारा अमेरिकी बाजार में भारत को उसके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में सही प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिए जाने के बाद इसे लागू किया जाएगा।

जयपुर, जोधपुर, कोटा में भाजपा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से बीकानेर ही एकमात्र ऐसा नगर निगम हैं, जहां पर कांग्रेस के महापौर बने हैं, बाकी 9 जगहों पर भाजपा के महापौर बने हैं। ज्ञात रहे कि गत 21 सितंबर को प्रदेश के 7 नगर निगम सहित, 303 निकायों में मेयर, चेयरमैन और अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। इन 7 नगर निगमों में से उदयपुर, अजमेर, अलवर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर में भाजपा के मेयर बने थे। शुक्रवार को जयपुर के महापौर चुनाव में भाजपा के सुनील कोठारी को 89 मत मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता मावर को 60 वोट मिले। एक पार्षद ने नोटा का चुनाव किया। यहां कुल 150 वार्ड हैं। इसी प्रकार, जोधपुर महापौर चुनाव में भाजपा के प्रसन्नचंद मेहता को 53 वोट मिले, उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार राजेन्द्र सोलंकी को 47 मत मिले। यहां कुल 100 वार्ड हैं।

इसी तरह, कोटा नगर निगम के महापौर चुनाव में भाजपा उम्मीदवार अनुसुइया गोस्वामी को 65 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता सुमन को सिर्फ 35 मत मिले। यहां 100 वार्डों में कांग्रेस के 39 पार्षद हैं, और भाजपा के 57 व 4 निर्दलीय हैं। ऐसे में कांग्रेस को सिर्फ 35 वोट मिलना साफ जाहिर करता है कि यहां कांग्रेस के 4 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है।

ज्ञानेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। कुछ कार्यक्रम मुख्य चुनाव आयुक्त की भूटान यात्रा के कारण भी स्थगित किए गए थे।

इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए कि एक दौरे पर 1.5 करोड़ रुपये तक खर्च हो सकते हैं, सूत्रों ने कहा कि यह खर्च केवल तब होता है जब कोई कार्यक्रम वास्तव में आयोजित किया जाता है।

जम्मु-कश्मीर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सदन द्वारा पारित प्रस्तावों के अलावा, यह सदन भारत सरकार से जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल और शीघ्र बहाल करने का आ ान करता है तथा यह प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का संकल्प लेता है।"

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908